

(11)

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे०मि० अपील सं० ०८/११-१२

परशुराम यादव एवं अन्य.....अपीलकर्ता ।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी ।

।।आदेश।।

06-09-2017

प्रस्तुत रे०मि० वाद सं० ०८/११-१२ परशुराम यादव एवं अन्य सा०, शितलपुर थाना तालझारी अंचल (जरमुण्डी) बनाम सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे०मि० वाद सं० ३१८/२०००-०१ में पारित आदेश दिनांक २३.०२.०४ के विरुद्ध में दायर किया गया है ।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया ।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा शितलपुर के खाता सं० ३ के अन्तर्गत दाग सं० ४११/४ रकवा ०-२-० (दो) कठ्ठा जमीन के साथ जमाबंदी सं० १४ के दाग सं० ९५/४ में रकवा ०-२-० (दो) कठ्ठा जमीन को सं०५० कास्तकारी अधिनियम के धारा २३ के अन्तर्गत आपस में बदलेन की स्वीकृति हेतु अपीलकर्ताओं द्वारा निम्न न्यायालय में एस०ई० वाद सं० १८/९९-२००० दायर किया गया । निम्न न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक २३.०७.९९ को उक्त बदलेन की स्वीकृति दी गई है । तत्पश्चात् इस आदेश के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा बदलेन जमीन पर बसगढ़ी करने हेतु निम्न न्यायालय में रे०मि० वाद सं० ३१८/२०००-२००१ दायर किया गया । इस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्ताओं को बदलेन जमीन पर बसगढ़ी का प्रतिवेदन दिया गया । एवं कोर्ट अमीन द्वारा उक्त जमीन का सीमांकन प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया । किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है । इसी आदेश के विरुद्ध में यह अपील दायर किया गया है ।

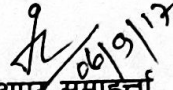
निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागज एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला अपीलकर्ताओं को एस०ई० वाद सं० १८/१९९९-२००० में प्राप्त बदलेन जमीन पर बसगढ़ी से संबंधित है जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्ताओं को बसगढ़ी दिया गया एवं वाद में पुनः कोर्ट अमीन द्वारा उसी जमीन का सीमांकन भी कर दिया गया है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है । जबकि अपीलकर्ताओं को जमीन बदलेन संबंधी आदेश पूर्व में ही एस०ई० वाद

fi

सं० 18/1999-2000 में आदेश दिनांक 23.07.1999 को पारित किया जा चुका है।

पुनः इस पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका सं०५० कास्तकारी अधिनियम के धारा 23 के तहत कार्रवाई करेंगे।
लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
दुमका।


अपर समाहर्ता,
दुमका।

(12)

DBA-38
18/17/17
Noted